



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
 भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
 प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]
 No. 122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली-4 मई, 2017

प्रारंभिक जाँच परिणाम

विषय :चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सेरामिक टेबलवेयर और चाकुओं और प्रसाधन मदों को छोड़कर किचनवेयर' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच

संख्या 14/05/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः ऑल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिसे आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निर्यातित "चाकुओं और प्रसाधन मदों को छोड़ कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर" (जिसे आगे सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जाँच की शुरूआत करने और पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 13.10.2016 की अधिसूचना संख्या 14/05/2016-डीजीएडी द्वारा अधिसूचना जारी की जिसमें पाटन-रोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटन-रोधी जाँच की शुरूआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा

और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पादों के पाटन का आरोप लगाया गया है।
- (2) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- (3) प्राधिकारी ने जांच को उचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा दायर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।
- (4) प्राधिकारी ने भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी है और उनसे जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया है।
- (5) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को भेजी थी।
- (6) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातिक प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर दिया है:-

- क. कांगफू सेरामिक मेनुफेक्चरिंग कंपनी
- ख. चांगसा जोयसेंट डिशवेयर कंपनी लिमिटेड
- ग. जिबो टाइमस्टोन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- घ. शंघाई फाइन-वी होमवेयर एंड गिफ्ट्स इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
- ड. बीआरटी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- च. होजिआंग सेरामिक शेनज्जेन कंपनी लिमिटेड
- छ. शेनज्जेन गोल्डनवाल सेरामिक कंपनी लिमिटेड
- ज. किनहुआंगडो एचडीटी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- झ. कारोसा चाइनावेयर (शेनज्जेन) कंपनी लिमिटेड
- ज. जिंगडेज्जेन एमशन पोर्सेलेन कंपनी लिमिटेड
- ट. हनडन फेंगफेंग शेनगुआन सेरामिक कंपनी लिमिटेड
- ठ. लेता इंटरनेशनल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ड. लिंटन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड(रिझाओ)
- ह. गुआंगसी युलिन सिटी जिआचाओ सेरामिक कंपनी लिमिटेड

(7) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना के संबंध में चीन के किसी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है।

(8) चाइना चैम्बर आफ कामर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ लाइट इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स एंड आर्ट क्राफ्ट्स ने विधिक अनुरोध किये हैं परंतु किसी भी सदस्य ने निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। समय-सीमा तथा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त समय-विस्तार के समाप्त होने के बाद पक्ष ने समय बढ़ाने की मांग की है। पक्षकार ने उसे उपलब्ध अवसर का लाभ नहीं उठाया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि पाटन-रोधी जांच के समयबद्ध होने के कारण उसमें निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित होता है ताकि उचित निर्धारण में प्राधिकारी को सहायता मिल सके। अतः अंतिम स्तर पर पक्षकार द्वारा समय बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। तथापि पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया गया और इस जांच परिणाम में उचित ढंग से समाधान किया गया है।

(9) नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए आयातक प्रश्नावली भेजी।

- क. के. एस. ओवरसीज
- ख. ईस्ट कोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
- ग. राज एजेंसीज
- घ. वाईएसआर इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
- ङ. वाल-मार्टइंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- च. वाइटगोल्ड ट्रेडिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
- छ. आईसीसी रियलटी (आई) प्राईवेट लिमिटेड
- ज. फ्यूचर रीटेल लिमिटेड
- झ. कृष्णा एंटरप्राइजेज
- ज. कर्मा ट्रेडिंग

(10) प्रत्युत्तर में, केवल एक आयातक मैसर्ज वाल-मार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर और विधिक अनुरोध प्रस्तुत किया है।

(11) इसके अलावा, जांच के बिल्कुल अंतिम स्तर पर मैसर्ज हैमिल्टन हाउसवेयर प्राईवेट लिमिटेड ने क्षति संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया है और इस जांच परिणाम में उनका उचित ढंग से समाधान किया गया है।

(12) जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना की प्रति याचिकाकर्ताओं सहित विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात भारतीय उत्पादकों/एसोसिएशनों को भी भेजी गई थी।

(13) प्रत्युत्तर में निम्नलिखित ने याचिका के समर्थन में अपने पत्र प्रस्तुत किए हैं:

- क. यश्वी एंटरप्राइजेज
- ख. अनिल फाइन सेरामिक
- ग. सम्राट सेरामिक्स
- घ. रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड

- ड. मारवल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- च. शी शेल सेरामिक्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
- छ. मुद्रिका सेरामिक्स (इंडिया) लिमिटेड
- ज. शान टेबलवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
- झ. फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- ज. ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
- ट. टाटा सेरामिक्स लिमिटेड

(14) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।

(15) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें और उसे नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाईल में रखा गया है।

(16) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई। जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

(17) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी विक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाठन मार्जिन से न्यूनतर पाठन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(18) यह जांच 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर 31 मार्च, 2016 (जांच अवधि) की अवधि में की गई थी। तथापि, क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जाँच में अप्रैल, 2012 - मार्च 2013, अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 - मार्च, 2015 और जांच की अवधि (जांच अवधि) को शामिल किया गया है।

(19) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच की अवधि समेत पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आकड़ों पर भरोसा किया है।

(20) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्कों और सूचना का उनके साक्ष्य से समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझी गई सीमा तक इस प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उचित ढंग से विचार किया गया है।

(21) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जांच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।

(22) इस प्रारंभिक जाँच परिणाम में *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

(23) संबद्ध जाँच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनायी गई विनिमय दर 1 अमरीकी डालर = 65.91 रुपये है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

- (1) आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति उत्पाद के बीच भारी गुणात्मक अंतर हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीयूसी की गुणवत्ता स्तरीय नहीं है।
- (2) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद विल्कुल मूलभूत हैं जबकि आयातित उत्पाद सभी मशीन निर्मित हैं और उनमें काफी अच्छी फिनिशिंग है घरेलू आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु को अनेक बार अस्वीकार किया गया है और घरेलू उद्योग की पैकिंग काफी घटिया है।
- (3) घरेलू आपूर्तिकर्ता एक ट्रक से कम वस्तु की आपूर्ति नहीं करते हैं जिससे मालसूची में वृद्धि होती है और वाल-मार्ट के विहितमानकों से अधिक संभलाई के दिन बढ़ जाते हैं।
- (4) चीन से वस्तुओं का आयात करने के कारण निम्नलिखित हैं:-
 - घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं
 - घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के पास उचित मशीनरी उपलब्ध नहीं है।
 - वस्तुओं की गुणवत्ता कोर्डराइट, सैगर, सेटर और नाइट्रोइट बांडेड सिलिकान कार्बाइड किल्न फर्नीचर का उपलब्ध नहीं होना।
 - प्राकृतिक गैस जैसे सस्ते ईंधन की अनुपलब्धता।
- (5) विचाराधीन उत्पाद काफी व्यापक है और उसमें असंबंधित उत्पाद शामिल हैं। सौदा-वार आयात आकड़ों के अनुसार सेनिटरी वेयर और टायलेट सीट को पीयूसी माना गया है।
- (6) स्पाइस मिल्स और सेरामिक ग्राइंडिंग हिस्सों को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इन मिलों का प्रयोग मानक टेबलवेयर जैसे कप और प्लेटों में होता है।
- (7) प्राधिकारी को उत्पाद के दायरे के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए।
- (8) घरेलू आपूर्तिकर्ता 'स्टूडियो पॉटरी' उपलब्ध कराने में असमर्थ है।

घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

6. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- (1) विचाराधीन उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर हैं।
- (2) मिट्टी के बर्तन, बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलेन-वेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में सेरामिक के किचेनवेयर और टेबलवेयर शामिल हैं।

(3) शेपिंग और उसके बाद गैर धात्विक खनिज की फायरिंग द्वारा निर्मित विभिन्न कठोर, ब्रिटल, ताप-रोधी और जंग-रोधी सामग्री जैसे क्ले, उच्च ताप पर सेरामिक्स होते हैं। बोन चाइना को केलिंश्यम फास्फेट (बोन एश), क्ले, फेल्सपार और क्वार्ट्ज पाउडर से विनिर्मित किया जाता है।

(4) विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि संबद्ध वस्तु के आयात एचएस कोडों 6911 और 6912 के अधीन 6 और 8 अंकीय स्तर पर विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। आयात आकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात 6911, 691110, 69111011, 69111019, 69111021, 69111029, 69119010, 6912, 69120010, 69120020, 69120030 और 69120040 जैसे विभिन्न सीमाशुल्क उपशीर्षों के अधीन किया जाता रहा है।

(5) उत्पाद में विभिन्न विशेषताएं जैसे शक्तिशाली हाइड्रोफोबिक और ओलियोफोबिक विशेषताएं काफी नान-स्टिक विशेषता सेरामिक सतह के लिए स्वच्छता संरक्षण काफी एब्रेशन रोधी कम समय में सूखना, प्रयोग के बाद तुरंत स्टोर किया जा सकता है, तापमान परिवर्तन रोधी कमरे के तापमान पर सूखना, रासायनिक और एब्रेशन रोधी, मितव्ययी प्रयोग के जरिए उच्च कार्यक्षमता (खपत: 5-10 मिली. प्रति वर्ग मी.²), खाद्य सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल, पूरी तरह से फ्रास्ट मुक्त हैं।

(6) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद एक समान है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आवेदक के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये दोनों भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

(7) आवेदकों का यह दावा कि उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है का पुरजोर खंडन किया गया है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग सर्वोत्तम मर्शीनों से युक्त है अर्थात रोलर हेड्स, आटो कप प्लांट और अत्याधुनिक, इंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल किल्न से सुसज्जित है। किल्न फर्नीचर, सेम्गर, कच्ची सामग्री, चाइना क्ले आदि की सर्वोच्च गुणवत्ता तत्काल उपलब्ध है। वास्तव में भारत में उत्पादित किल्न फर्नीचर और कच्ची सामग्री गुणवत्ता में इतनी अच्छी है कि उसका निर्यात विभिन्न देशों को किया जाता है। गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को बाहर रखने का पर्याप्त औचित्य नहीं हो सकता है जैसा डीएसएम आईडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना है और माननीय सेस्टेट द्वारा उसका समर्थन किया गया है।

(8) विचाराधीन उत्पाद का दायरा व्यापक नहीं है बल्कि ओपेल ग्लासवेयर, मेलामाइन उत्पादों, सेरामिक इंसुलेटर्स जैसी अन्य जांचों के समान है।

(9) विश्व व्यापार संगठन के निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित समझे गए तरीके से विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित कर सकते हैं।

(10) यदि आयातित वस्तु बेहतर रंग और डिजाइन की हैं और अधिक नवोन्मेषी हैं तो उसकी कीमतें घरेलू उत्पादकों से बेहतर होनी चाहिए परंतु वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

(11) घरेलू उत्पादों को अस्वीकार करने संबंधी आरोप बिलकुल निराधार हैं। वालमार्ट अब भी घरेलू उत्पादकों से सिरेमिक टेबलवेयर लेता है।

(12) घरेलू उद्योग स्टूडियो पॉटरी का विनिर्माण कर रहा है और फ्यूचर ग्रुप (बिग बाजार), लाइफ स्टाइल, गुड अर्थ, शार्पर्स स्टाप आदि जैसी अनेक भारतीय रीटेल शृंखलाओं को उनकी आपूर्ति कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को 'चाकू और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर' (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु या पीयूसी भी कहा गया है) हैं।

8. यह नोट किया जाता है कि बोन चाइना, स्टोनवेयर और पोर्सलेन-वेयर सभी सेरामिक उत्पाद हैं और इसलिए विचाराधीन उत्पाद में बोन चाइना, स्टोन और पोर्सलेन के किचेन वेयर और टेबलवेयर शामिल हैं। सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद का प्रयोग खाना खाने, पानी पीने और खाना और पेयों को परोसने और घरों और होटलों में सजावट के लिए भी किया जाता है।

9. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध लागत में भारी अंतर वाले विभिन्न ग्रेडों में उत्पादित नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे चम्मच, कटोरी, प्लेट आदि को कैल्शियन, क्वार्टज, फेल्सपास और चाइना क्ले के मिश्रण से उत्पादित किया जाता है। विभिन्न प्रकारों के उत्पादन का अर्थ केवल इस मिश्रण को वांछित आकार देना है। इसलिए इन सभी मदों को एक व्यापक शीर्षक 'सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पाद' में वर्गीकृत करना उचित समझा गया है। 'सभी प्रकार के ओपेल ग्लासवेयर' और मेलामाइन टेबलवेयर और किचनवेयर उत्पादों नामक उत्पाद के लिए इसी प्रकार के मामले रहे हैं।

10. याचिकाकर्ताओं द्वारा स्टूडियो पॉटरी की आपूर्ति किए जाने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने स्टूडियो पाटरी की आपूर्ति के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को वस्तुतः गलत पाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी की परिभाषा और दायरा जांच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना में और पीयूसी संबंधी अनंतिम निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

11. प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि विचाराधीन उत्पाद को भार के अनुसार बताना उचित होगा क्योंकि आयात के समय और कारखाने से विक्रेता तक सौदे मुख्यतः भार के अनुसार किए जाते हैं। इसके अलावा यह देखा गया है कि उत्पाद की 50-60 प्रतिशत लागत कच्ची सामग्री और सुविधाओं पर होती है। कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत उत्पाद के भार से समानुपाती होती है; इसलिए उत्पादन की लागत उत्पाद के भार के अनुरूप होती है। डीजीसीआईएस के अधिकांश आकड़े भार के अनुसार उपलब्ध हैं और समस्त विश्लेषण भार के अनुसार किया गया है।

12. संबद्ध वस्तु का कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है और इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 69 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके आयात एचएस कोडों 6911 और 6912 के अधीन हो रहे हैं। तथापि एचएस कोड केवल सांकेतिक है और उत्पाद का वर्णन वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निर्धारक कारक है।

13. अतः वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'चाकूओं और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर' है।

समान वस्तु

14. पाटन-रोधी नियमावल के नियम 2 (घ) में सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।

15. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद और भारत में आयातित उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच गुणवत्ता संबंधी कथित अंतर दर्शने के लिए कोई तथ्यपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता में अंतर तब तक पहचाना नहीं जा सकता है जब तक अंतर के तथ्य न बताये जाएं और उनका प्रभाव न दर्शाया जाए। प्राधिकारी 2000 में सूचित 'डीएसएम आईडेमिसु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी' (119) ई.एल.टी. 308 के मामले में सेस्टेट के निर्णय को भी नोट करते हैं जिसमें न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार माना था ।

'चूंकि अपीलीय काउंसेल की दलील संतोषजनक नहीं है उन्होंने विनिर्माण की प्रक्रिया के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य/तकनीकी साहित्य प्रस्तुत नहीं किया जो दर्शाता हो कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत में निर्यातित उत्पाद से भिन्न है... गुणवत्ता में अंतर किसी उत्पाद को भिन्न नहीं बनाता और निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह समुक्ति सही है कि यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग-अलग है, का यह अर्थ नहीं है कि आयातित और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं।'

16. वस्तु के आयात के कारण के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देश से आयात किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और आयातित संबद्ध उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

18. इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

- (1) प्रस्तुत किया गया पाटन-रोधी आवेदन पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 का स्पष्ट उल्लंघन है।
- (2) विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्रों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पत्रों के गहन पाठ से यह देखा जा सकता है कि समर्थन पत्र उत्पादकों के अलग समूह द्वारा अलग पाटन-रोधी जांच के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उस तरह से आवेदकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।
- (3) जांच को इसलिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसे उद्योग को स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं है।
- (4) आवेदकों को समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा बनता है, इसलिए वह पात्र घरेलू उद्योग नहीं हैं।
- (5) प्राधिकारी समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों की प्रवृत्ति को समझने के लिए अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों को भी जोड़ सकते थे।
- (6) यदि आवेदकों का कुल उत्पादन 25 प्रतिशत से अधिक भी है परंतु यह बात आवेदन के योग्यता के संबंध में है और न कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ है।

घरेलू उद्योग के विचार

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- (1) यह याचिका भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादकों की ओर से आँल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात् क्ले क्राफ्ट(आई) प्राईवेट लिमिटेड, भारत पोटरीज लिमिटेड, सेरामिक टेबलवेयर लिमिटेड, और यूपी सेरामिक्स एंड पोटरीज प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें याचिकाकर्ता/ आवेदक कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चाकुओं और प्रसाधन मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन दायर किया है।
- (2) याचिकाकर्ता के अलावा कुछ उत्पादकों ने याचिका का समर्थन किया है। समर्थन के पत्र यश्वी एंटरप्राइजेज, अनिल फाइन सेरामिक, सप्लाट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लिमिटेड, शान टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड और टाटा सेरामिक्स लिमिटेड से मिले हैं।
- (3) याचिकाकर्ताओं का भारतीय उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है। इसके अलावा, उन्हें अनेक विनिर्माताओं का समर्थन मिला है जिससे उनका उत्पादन में कुल प्रतिशत हिस्सा 60 प्रतिशत हो गया है, इस प्रकार याचिकाकर्ता कंपनियां कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनाती हैं और पाटनराधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर शामिल हैं।
- (4) याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देश से न तो को आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातिक या भारत में किसी आयातक से (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) संबंधित हैं।
- (5) समर्थकों ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से सेरामिक किचनवेयर और टेबलवेयर के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की याचिका का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21. पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

22. यह याचिका भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से आँल इंडिया पोटरी मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमपीए) और इंडियन सेरामिक सोसाइटी (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। कुछ भारतीय उत्पादकों अर्थात् (क) क्ले क्राफ्ट(आई) प्राईवेट लिमिटेड, (ख) सेरामिक टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, (ग) भारत पोटरीज लिमिटेड और (घ) मैसर्ज यूपी सेरामिक्स एंड पोटरीज प्राईवेट लिमिटेड (जिन्हें याचिकाकर्ता/ याचिकाकर्ता एसोसिएशन कहा गया है) ने आवश्यक लागत और वित्तीय सूचना प्रदान की है। अनेक अन्य उत्पादकों अर्थात् यश्वी एंटरप्राइजेज, अनिल फाइन सेरामिक, सप्लाट सेरामिक्स, रघुवीर (इंडिया) लिमिटेड, मारवेल सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, शी सेल सेरामिक्स (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, मुद्रिका सेरामिक्स (आई) लिमिटेड, शान टेबलवेयर प्राईवेट लिमिटेड, फेदर टच सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड, ओसिस सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड और टाटा सेरामिक्स लिमिटेड ने याचिका का समर्थन किया है।

23. सेंट्रल ग्लास एंड सेरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर) द्वारा दिए गए आकड़ों के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने संगठित क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में उत्पाद के उत्पादकों के ब्योरे का उल्लेख किया है।

विवरण	मी. टन	भारतीय उत्पादन में हिस्सा %
	जांच अवधि	जांच अवधि
समग्र रूप से याचिकाकर्ता	8,652	31%
समग्र रूप से समर्थक	8,650	31%
याचिकाकर्ता + समर्थक समग्र रूप से	17,302	62%
अन्य	10,700	38%
भारतीय उत्पादन	28,002	100%

24. इसके अलावा, याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।

25. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों के उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियां पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. विभिन्न प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है :

- आवेदकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है और उन्होंने उत्पादन मात्रा, घरेलू बिक्री मात्रा, निर्यात बिक्री मात्रा, मालसूची की मात्रा, सूचीबद्ध रूप में सीओपी प्रति इकाई, बिक्री कीमत प्रति इकाई सूचीबद्ध, लाभ/(हानि) प्रति इकाई सूचीबद्ध, रोजगार, उत्पादकता, प्रतिशत में आरओसीई, प्ररूप IV- ख, लागत संबंधी सूचना और वित्तीय परिणामों के आरओसी अंश के संबंध में सूचना नहीं बताई है।
- ऐसी सूचना प्रदान नहीं करना पाटन-रोधी नियमावली में दिए गए गोपनीयता संबंधी प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। काफी सूचना को कोई औचित्य बताए बिना गोपनीय रखा गया है।

घरेलू उद्योग के विचार :

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं

- घरेलू उद्योग ने पाटन-रोधी नियमावली के मानकों के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और वास्तव में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और उनके अनुरोध पर उचित टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने नियम 6 (7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन 7-रोधी नियमावली के नियम-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना, (1) नियम 6 के उपनियम (7), (2), नियम 12 के उपनियम (2) (3), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दें सकते हैं।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों का एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा। इस अनंतिम जांच परिणाम में विभिन्न चर्चाएं गोपनीयता के पहलू के संबंध में घरेलू उद्योग की अन्य दलीलों के संबंध में स्वतः-स्पष्ट हैं।

ड. विविध मुद्दे

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

31. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है:-

(1) यह याचिका जनवरी 2016 में दायर की गई और आकड़े मार्च 2016 तक प्रदान किए गए। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रदत्त आकड़ों की पर्याप्तता और सटीकता की जांच नहीं की है।

(2) घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले की सूचना के बावजूद अपनी सूचना प्रदान नहीं की है इसलिए उसे पाटन-रोधी नियम के नियम 6(8) के अधीन असहयोगी माना जाना चाहिए।

(3) समर्थकों का सूचना प्रदान नहीं करना दर्शाता है कि उन्होंने प्राधिकारी के समक्ष क्षति के केवल असाक्ष्यांकित दावे किए हैं।

(4) आयात मूल्य में परिवर्तन और मात्रा संबंधी विश्लेषण के लिए अपनायी गई पद्धति असमर्थित धारणा पर आधारित हैं। पीयूसी को भार के अनुसार मापा/मात्रात्मक किया गया है जबकि आयात आकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश आयात इकाइयों/नगों में सूचित की गई है।

(5) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी करार के अनुच्छेद 12.1 के उल्लंघन में कार्रवाई की है क्योंकि वह जांच शुरूआत से पहले हितबद्ध पक्षकारों को यह सूचित नहीं कर पाये हैं कि प्राधिकारी संतुष्ट हैं और जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

(6) याचिकाकर्ता पाटन और क्षति निर्धारण पर भरोसा की गई सूचना के स्रोत को बताने में विफल रहे हैं।

(7) डीजीसीआईएंडएस के आकड़े एक्सेल प्ररूप में हैं अपरिष्कृत और शोधित रूप में अपनायी गई पद्धति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

घरेलू उद्योग का विचार :

32. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- (1) चीन के निर्यातकों ने जांच की शुरूआत के बाद अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद कोई सूचना प्रदान करके सहयोग नहीं किया है। किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- (2) चीन की उत्पादक/निर्यातक एसोसिएशन जो पाटन-रोधी मामलों में उनके मामलों में पक्ष रखने के लिए निर्यातकों की मदद करते हैं, ने भी लागत और निर्यात से संबंधित विस्तृत सूचना प्रदान करके सहयोग नहीं किया है। चीन की एसोसिएशन को असहयोगी माना जाना चाहिए।
- (3) याचिकाकर्ताओं ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों को अपनाया है, उन्हें याचिका की एनसीवी प्रति में भी प्रदान किया गया है। आयातों का एक बड़ा हिस्सा भार के रूप में है और अन्य इकाइयां जैसे संख्या/नग/सेट को आयात आकड़ों के समग्र कारगर विश्लेषण के लिए भार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा पीयूसी का कारखाना द्वारा स्तर पर भार के रूप में सौदा किया गया है। इसलिए माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया जाना उचित है और प्रतिवादी पक्ष ने कोई वैकल्पिक पद्धति बताए बिना उस पर आपत्ति जताई है।
- (4) प्राधिकारी ने अधिसूचना द्वारा वर्तमान जांच की शुरूआत के बारे में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया था।
- (5) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा विधि के अधीन विहित आवश्यक लागत/वित्तीय सूचना प्रदान की गई है। समर्थक जो पाटन के प्रभाव के कारण नुकसान उठा रहे हैं और उन्होंने याचिका का समर्थन किया है, के लिए लागत/वित्तीय आकड़ों को देना अपेक्षित नहीं है।
- (6) चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के अनुसार बाजार आसूचना और मानक प्रथाओं के अनुसार निर्यात कीमत में आवश्यक समायोजनों के साथ निर्धारित किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. विविध मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की जांच और निम्नानुसार समाधान किया गया है:-

- (1) प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन में जांच की शुरूआत करने के लिए समस्त संगत सूचना शामिल थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर ही कि आवेदन में जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद आवेदक से संभव समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी और उसका सत्यापन भी किया है।
- (2) प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि पीयूसी को भार के रूप में व्यक्त करना उचित होगा क्योंकि आयात तथा कारखाना से डीलर, दोनों ओर सौदे भार के अनुसार किए जाते हैं। कच्ची सामग्री और सुविधाओं की लागत उत्पाद के भारत के सीधे अनुपात में हैं इसलिए उत्पादन लागत उत्पाद के भार के बिल्कुल अनुरूप है। डीजीसीआईएंडएस के अधिकांश आकड़े भार के अनुसार उपलब्ध हैं और संख्या/सेटों/नग में उपलब्ध शेष आकड़ों को भार में परिवर्तित किया गया है और समस्त विश्लेषण किए गये हैं।
- (3) प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया। इसके अलावा, प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत को अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक अधिसूचना प्रकाशित की।

(4) इस तर्क के संबंध में कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने सूचना प्रदान नहीं की है या समर्थकों ने सीमित सूचना प्रदान की है, यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर करना होता है। वर्तमान मामले में, एक बार यह निर्धारित होने पर कि याचिकाकर्ता कंपनियां घरेलू उद्योग हैं, पाटन-रोधी नियमावली में ऐसी कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि अन्य भारतीय उत्पादकों की सूचना पर भरोसा किया जाए।

(5) प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आकड़ों को एनसीवी याचिका के भाग के रूप में सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया था। विश्लेषण के लिए आकड़ों का यथोचित सम्मान किया गया है। इसके अलावा, बाद के पैरा में यथा उल्लिखित एनईपी और पहुंच मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न गणनाएं बाद में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निदेशालय में अपनाई गई पद्धति और मानक प्रथाओं के अनुसार की गई हैं।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार और सामान्य मूल्य

34. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) (ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:-

"व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातिक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातिक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा।

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

घरेलू उद्योग के विचार

35. याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

(1) चीन जनवादी गणराज्य को पूर्ववर्ती मामलों में प्राधिकारी द्वारा और अन्य देशों में जांच कर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनायी गई स्थिति गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(2) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों :-

क. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जबकि एक प्रमुख शेयरधारक राज्य स्वामित्व/नियंत्रित कंपनी है।

ख. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य दर्शाती हों।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है।

घ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता यदि मापदंडों में से एक भी पूरा न हो।

ङ. यह दायित्व चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का है न कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में काम कर रहे हैं।

च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें।

छ. ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं अपितु उसे किसी अन्य पक्ष से अधिग्रहीत किया है बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी न हो और दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध न हो।

(3) इन नियमों के अनुसार, चीन में सामान्य मूल्य को निम्नलिखित आधारों में से किसी एक से निर्धारित किया जा सकता है :

- बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर,
- बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य,
- ऐसे किसी तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों की कीमत
- भारत में वास्तव में प्रदत्त कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके
- भारत में वास्तव में देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके।

(4) चूंकि चीन की किसी कंपनी द्वारा प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया गया है इसलिए संबद्ध देश को गैर-बाजार वाली अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।

(5) चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात कीमत को बाजार आसूचना और मानक प्रथाओं के अनुसार निर्यातक कीमत के लिए आवश्यक समायोजनों के साथ डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों का सारांश निम्नानुसार है :-

- (1) सामान्य मूल्य के निर्धारण में याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा परिकल्पित पद्धति पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अधीन निर्धारित उपबंधों के उल्लंघन में है।
- (2) निर्यात कीमत का निर्धारण और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन किसी साक्ष्य के बिना किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

गैर बाजार अर्थव्यवस्था देशों से संबंधित उपबंध

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अधीन निर्धारित संगत उपबंध निम्नानुसार हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" शब्द का अर्थ ऐसा कोई देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागत या कीमत निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन करते हुए निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार पण्य वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करती हैं।

(2) ऐसी एक परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा,

बशर्ते कि तथापि यह कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे देश की संबंधित फर्मों निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आशय की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी किसी परिकल्पना का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या:-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टेखातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चिंतता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

बशर्ते कि फिर भी जहां इस पैरा में विनिश्चित मानदंड के आधार पर लिखित साक्ष्य द्वारा ऐसा दर्शाया गया है कि एक अथवा अधिक ऐसी फर्मों के लिए पाटन-रोधी जांच के अध्यधीन बाजार की दशाएं विद्यमान हैं, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में उल्लिखित सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

38. जांच प्रारंभ करने के चरण में, प्राधिकारी ने एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में चीन जन गण को मानने के अनुमान के साथ कार्रवाई शुरू की। जांच प्रारंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच प्रारंभ होने की सूचना का उत्तर देने तथा उनकी बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के निर्धारण से संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी की प्रश्नावली की प्रति भेजी। प्राधिकारी ने चीन सरकार से उनके देश के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सलाह देने का भी अनुरोध किया। हालांकि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादकों और निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नावली का उत्तर इस प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरू होने की सूचना के फलस्वरूप प्रस्तुत नहीं किया और न ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन किया। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ कार्रवाई शुरू करना उपयुक्त समझते हैं। चूंकि, चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्राधिकारी प्रस्तावित निर्धारण के उद्देश्य से चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने में सक्षम नहीं हैं।

40. इस तथ्य को देखते हुए कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी प्रश्नावली सहित निर्यातक की किसी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, एमईटी का दर्जा चीन के उत्पादकों को नहीं दिया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस प्राधिकारी को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करने के लिए कोई ठोस तथ्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। इस कारण से प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखकर अन्य उचित आधार पर चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

41. उपर्युक्त को देखते हुए, चीन जन गण से भारत में आयात किए गए संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की लागत के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ मार्जिन के लिए उचित वृद्धि करने के बाद 'किसी अन्य आधार' पर किया गया है। सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के सबसे प्रभावी घटक के लिए अनुमति दिए गए स्तरों पर प्रमुख कच्चे माल की खपत, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि पर विचार करने के बाद तय किया गया है। ब्याज को छोड़कर बिक्री की लागत का 5 प्रतिशत उचित लाभ के लिए जोड़ा गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का एक्स-वर्क सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित रूप में और तरीके से इस प्राधिकारी को सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत और अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

43. निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन संबंधी खर्चे और अंतर्देशीय भाडा प्रभार के कारण कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत तय करने के लिए किया गया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात के लिए कारखाना-गत स्तर पर निबल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

44. उपयुक्त पद्धति के आधार पर संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातिकों के मामले में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया जाता है:-

विवरण	जांच अवधि	
	रुपए/किग्रा.	डॉलर/किग्रा.
संरचित सामान्य मूल्य	***	***
निवल निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	86.17	1.31
पाटन मार्जिन - %	***	***
पाटन मार्जिन % (रेंज)	***	***

छ. क्षति निर्धारण एवं क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

45. प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग को मात्रा के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि में विक्री 12 प्रतिशत तक बढ़ी है। उद्योग ने विक्री के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- (2) ऐसे उत्पादक जिसका कार्य निष्पादन बहुत खराब हो गया है, ने प्राधिकारी को अपेक्षित आंकड़े/सूचना प्रदान नहीं करके एक उचित निर्धारण करने में कोई सहायता नहीं की है।
- (3) आवेदक जांच की अवधि में अपने कुल उत्पादन का 93 प्रतिशत विक्री करने में सक्षम रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई क्षति नहीं हुई है।
- (4) घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। संबद्ध वस्तुओं का आयात अन्य घरेलू उत्पादकों की विक्री में कमी की सीमा तक बढ़ा है।
- (5) मांग आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए आयात किए गए थे। घरेलू उत्पादकों को घरेलू बाजार में मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने में असफलता के कारण क्षति हो रही है।
- (6) कीमत के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है। आवेदकों द्वारा इकाइयों/टुकड़ों में निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं का भार और पाटित सामान की परिणामी कीमत तय करने के लिए अपनाई गई पद्धति दोषपूर्ण है।

(7) आयात के कारण कीमत का कोई दमन/हास नहीं हुआ है। आवेदक की निवल विक्री वसूली संबद्ध वस्तुओं की लागत की तुलना में अधिक है।

(8) आवेदक कीमत की लागत में वृद्धि की तुलना में अपनी विक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहे हैं।

(9) आवेदकों की कार्यशील पूँजी क्षति की अवधि के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है। कार्यशील पूँजी में इस प्रकार की वृद्धि अविश्वसनीय और काल्पनिक है।

(10) घरेलू उद्योग को कथित पाटन एवं क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आवेदकों ने मांग में वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए क्षमताओं में वृद्धि की है। लेकिन क्षति की अवधि की जांच के दौरान मांग स्थिर रही है।

(11) घरेलू बाजार के अन्य उत्पादकों को कोई क्षति नहीं हुई है और वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घरेलू उत्पादकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(12) आवेदक यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग को कथित पाटन के कारण क्षति हो रही है।

(13) घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति अथवा क्षति का खतरा - आरोप, कथन अथवा अनुमान पर ही आधारित है।

(14) प्रत्येक छः महीने में कीमत वृद्धि की गई है।

(15) ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जहां घरेलू आपूर्तिकर्ताओं ने आदेश दी गई मात्रा से कम वस्तु की आपूर्ति की है और वे निर्धारित अवधि के भीतर वाल-मार्ट को वस्तुओं की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

(16) इस याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस आधार पर, पाटनरोधी शुल्क की मांग करना कि मांग में वृद्धि धीमी है, पूर्ण रूप से अनावश्यक है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

(17) कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है क्योंकि सूचीबद्ध निवल विक्री प्राप्ति 2012-13 में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 106 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।

(18) कथित पाटित आयात का घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। याचिकाकर्ता कीमत में कटौती अथवा कीमत में हास अथवा न्यूनीकरण को सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

(19) विक्री की लागत में भी जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(20) याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और घरेलू विक्री में भी वृद्धि हुई है।

(21) क्षमता उपयोग में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन वह कथित पाटन के कारण नहीं, बल्कि बढ़ी हुई स्थापित क्षमता के कारण हुई है।

(22) याचिकाकर्ता 2012-13 में घाटा उठाने वाली कंपनी से 2013-14 से आगे जांच की अवधि तक बहुत अधिक लाभ कमाने वाली इकाई बन गई है।

(23) जांच की अवधि के दौरान मजदूरी में वृद्धि हुई है। ऐसा कोई भी आर्थिक कारक नहीं प्रतीत होता है कि जिसने भारत में विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला हो।

(24) आवेदक पर्याप्त क्षति के खतरे के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं रहे हैं अथवा पर्याप्त क्षति के खतरे का कोई भी कारक कथित पाटन के कारण मौजूद नहीं है।

(25) प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम जैसे कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताईवान और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए पॉलिएस्टर स्टेपल फाईबर के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच और चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए फ्लोगलास के अंतिम जांच परिणाम की चर्चा की है और प्राधिकारी ने आर्थिक मानदंडों के महत्व को दर्शाया है तथा यह माना है कि केवल

पाटन का मौजूद होना पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की जानी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

(26) इन आवेदकों की स्थापित क्षमता घरेलू बाजार में मांग की तुलना में कम थी। मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए आयात किए गए थे।

(27) घरेलू उद्योग का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है और यह लाभ अर्जित कर रहा है। कीमत में कटौती मात्र घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(28) घरेलू उद्योग के लाभ में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

घरेलू उद्योग के विचार

46. घरेलू उद्योग द्वारा संक्षेप में किए गए क्षति संबंधी अनुरोध निम्नलिखित हैं:-

- (1) क्षति की अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।
- (2) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात प्रस्तावित जांच की अवधि के आधार वर्ष से लगभग दोगुना हो गया है। चीन से आयात में क्षति की अवधि के दौरान भारत में कुल आयात और खपत तथा उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- (3) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में थोड़ी वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय उत्पादकों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है। दूसरी ओर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि का लाभ नहीं उठा सका है।
- (4) संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहा है और क्षति की अवधि के दौरान कीमत की कटौती में वृद्धि हुई है। आयातों का पहुँच मूल्य क्षति की अवधि दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत अधिक कम रहा है।
- (5) आयातों के पहुँच मूल्य में वर्ष 2013-14 में वृद्धि हुई है और तब क्षति अवधि में उसमें गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2014-15 तक वृद्धि हुई है और तब जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है, जिससे पाटित आयातों का कीमत न्यूनीकरण प्रभावित हुआ है।
- (6) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन और बिक्री की मात्रा में यह वृद्धि, देश में उपलब्ध क्षमताओं के स्तर और मांग पर विचार करने के बाद मामूली है।
- (7) विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाए जा रहे अत्यधिक पाटन के कारण प्रस्तावित क्षति की अवधि में क्षमता का कम उपयोग हुआ है जिसके फलस्वरूप भारतीय उत्पादकों द्वारा अपेक्षाकृत कम मात्रा में बिक्री की गई है।
- (8) पर्याप्त घरेलू उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के बावजूद उपभोक्ता संबद्ध देश से पाटित आयातों के साथ अपनी मांग को पूरा करना जारी रखता है, जिसके फलस्वरूप मात्रा मानदंड के मामले में अपेक्षा से कम कार्य निष्पादन हुआ है।
- (9) क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है। वैसी ही प्रवृत्ति घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी के प्रवाह और नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ के निष्पादन में देखी गई थी। तथापि, माल भंडार में और बिक्री की लागत में वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति पर दबाव पड़ा है।
- (10) अन्य देशों से आयातों का बाजार का हिस्सा पूरी प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान बहुत कम रहा है, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयातों के बाजार का हिस्सा पूरी प्रस्तावित क्षति अवधि के दौरान बहुत कम रहा है।

(11) प्रति कर्मचारी उत्पादन के मामले में माप की गई घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के साथ रोजगार के स्तर में वर्ष 2013-14 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद उसमें गिरावट आई है। वर्ष 2014-15 तक मजूदरी में वृद्धि हुई है और उसके बाद प्रस्तावित जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

(12) घरेलू उद्योग के पास विचाराधीन उत्पाद के माल भंडार में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(13) मात्रा और कीमत मानदंडों के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि अपेक्षा से कम रही है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, दोनों प्रस्तावित जांच की अवधि में सकारात्मक एवं अधिक हैं।

(14) भारतीय उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, लेकिन भारतीय उद्योग पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण क्षमता उपयोग में सुधार लाने में सक्षम नहीं है। मांग आपूर्ति का अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है। विदेशी उत्पादकों को भारतीय मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इन वस्तुओं का पाटन नहीं करना चाहिए।

(15) विरोधी पक्षकार मांग और आपूर्ति के अंतर का उल्लेख कर रहे हैं और दूसरी ओर क्षमता की वृद्धि पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्षमता में वृद्धि हुई थी, क्योंकि मांग में पूरी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(16) क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है क्योंकि पाटित आयातों की मात्रा ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है, कीमत में कटौती, कीमत ह्रास, बदतर लाभ ने इस उद्योग को अपना उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग बढ़ाने से रोका है। विकास के मानदंड नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

(17) संबद्ध वस्तु का विपणन माध्यम ऐसा है कि घरेलू उत्पादकों को इस उत्पाद को व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेचने की आवश्यकता है जो इसे उनके लिए इस वस्तु की कीमत को कम करना असंभव बना देता है और यदि चीन से आयात अपेक्षाकृत कम कीमत पर हो तब इसकी ओर स्पष्ट रूप से उपभोक्ता आकर्षित होंगे जिसके फलस्वरूप और अधिक आयात होगा। ये अंतिम उपभोक्ता नहीं हैं, जिन्हें इतनी अधिक कीमत पर आयात का लाभ मिल रहा है।

(18) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य कारकों का उल्लेख किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सकते हैं।

(19) कीमत में वृद्धि का आरोप निराधार है। प्रश्न यह है कि कितनी बार कीमत में वृद्धि को वाल-मार्ट द्वारा स्वीकार किया जाता है। घरेलू उद्योग ने विभिन्न लागत कारकों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और कम्बे माल की कीमतों में विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, जो कि एक वर्ष अथवा दो वर्ष में एक बार होता है, के आधार पर कीमत में वृद्धि होने का दावा किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

47. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों का ध्यान रखा है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान इस प्रकटन के संगत पैराओं में किया गया है।

48. इसके नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण स्वतः इन हितबद्ध पक्षकरों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

49. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग के पास इस देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि इस देश में मांग और पूर्ति में अंतर है, तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद को लाकर इस देश में उस अंतर को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। मांग और आपूर्ति में अंतर इस उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

50. क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रभाव तथा सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, पर इसके प्रभाव की जांच क्षति के मौजूद होने तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, का मूल्यांकन करने के लिए की है।

झ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

(क) आयात मात्रा

51. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने माप की एक उपयुक्त इकाई के रूप में भार पर विचार किया है। डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों की जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में कुल लेन-देन का लगभग 46 प्रतिशत लेन-देन है, जहां आयात की मात्रा की सूचना भार के आधार पर दी गई है। तथापि, शेष आयात अनेक अन्य इकाईयों नामतः संख्या, समुच्च्य, दर्जन, टुकड़े और किलोग्राम में है। भार के आधार पर आयात के लेन-देन को अपनाया गया है क्योंकि यह विश्लेषण के लिए है। प्रति इकाई औसत आयात कीमत का निर्धारण भार के आधार पर सूचित किए गए आयात के मूल्य और लेन-देन की मात्रा पर विचार करने के बाद किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित प्रति इकाई औसत आयात कीमत पर विचार किया जाता है, जबकि उन लेन-देन, जिनकी सूचना भार को छोड़ कर इकाईयों में की गई है, भार में दी गई है, जिसके द्वारा 100 प्रतिशत सूचित किए गए आयात, लेन-देन पर विचार विश्लेषण करने के लिए किया गया है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा नीचे दी गई है:-

आयात	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Ph चीन	मीट्रिक टन	5,519	6,596	9,114	10,160
कोई अन्य देश	मीट्रिक टन	849	972	810	836
कुल आयात	मीट्रिक टन	6,368	7,568	9,924	10,996

52. यह देखा गया है कि संबद्ध देश के आयात में क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) मांग और बाजार का हिस्सा

53. संबद्ध वस्तुओं की मांग/स्पष्ट खपत का निर्धारण सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात और घरेलू विक्री को जोड़ कर किया गया है।

मांग	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
घरेलू उद्योग की विक्री	मीट्रिक टन	7,791	7,870	7,948	8,375
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	मीट्रिक टन	19,752	18,361	16,795	15,269
भारतीय उत्पादकों की विक्री	मीट्रिक टन	27,543	26,231	24,743	23,644
चीन से आयात	मीट्रिक टन	5,519	6,596	9,114	10,160
कोई अन्य देश आयात -	मीट्रिक टन	849	972	810	836
मांग/खपत	मीट्रिक टन	33,911	33,799	34,667	34,640
मांग में बाजार का हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	23%	23%	23%	24%
अन्य भारतीय उत्पादक (समर्थकों सहित)	%	58%	54%	48%	44%
भारतीय उत्पादक समग्र रूप में	%	81%	78%	71%	68%
चीन	%	16%	20%	26%	29%
अन्य देश	%	3%	3%	2%	2%

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और यह समग्र क्षति अवधि में एक समग्र सकारात्मक प्रगति का भी दर्शा रहा है, जबकि विचाराधीन उत्पाद की मांग, आधार वर्ष से 2 प्रतिशत तक बढ़ गई और उसी अवधि में चीन से आयात में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

55. इस प्रकार से यह देखा गया है कि भारतीय मांग में संबद्ध देशों के आयातों का हिस्सा क्षति की अवधि के दौरान 16 प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा स्थिर रहा है और भारतीय उद्योग के बाजार के हिस्से में समग्र रूप से बहुत अधिक गिरावट आई है।

II. उत्पादन के संबंध में पाठित आयातों का हिस्सा

56. प्राधिकारी यह देखते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में भारत में उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चीन से आयात	मीट्रिक टन	5,519	6,596	9,114	10,160
कुल आयात	मीट्रिक टन	6,368	7,568	9,924	10,996
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मीट्रिक टन	8,128	8,313	8,364	8,652
भारतीय उत्पादन	मीट्रिक टन	30,510	30,069	28,283	28,002
निम्नोक्त के संबंध में संबद्ध देश का आयात हिस्सा					
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	68%	79%	109%	117%
भारतीय उत्पादन	%	18%	22%	32%	36%

(क) कुल आयातों के संबंध में आयात

57. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में कुल आयातों की तुलना में वृद्धि हुई है।

आयात	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
चीन	मीट्रिक टन	5,519	6,596	9,114	10,160
कोई अन्य देश	मीट्रिक टन	849	972	810	836
कुल आयात	मीट्रिक टन	6,368	7,568	9,924	10,996
कुल आयात में हिस्सा					
चीन	%	87%	87%	92%	92%
कोई अन्य देश	%	13%	13%	8%	8%

58. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संबद्ध देश से आयातों के हिस्से ने बाजार के हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यह स्वतंत्र रूप से तथा भारत में उत्पादों और खपत दोनों की तुलना में बढ़ा है।

ज. घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का कीमत प्रभाव

59. जहां तक कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-2 (2) में प्रावधान निम्नानुसार निर्धारित है:-

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाठित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक हास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती”

60. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाठित आयातों द्वारा बहुत अधिक कीमत में कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों में हास होता अथवा

कीमत में वृद्धि रूक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हुआ होता। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में हास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

कीमत में कटौती

61. यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या आयात इस बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, प्राधिकारी ने आयात की पहुँच कीमत की तुलना, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। इस संबंध में इस उत्पाद के पहुँच मूल्य और व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों को जोड़ कर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच की गई है। घरेलू उद्योगकी कीमतों का निर्धारण कारखाना-गत के स्तर पर किया गया था।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयात की पहुँच कीमत	रुपए/किग्रा.	119	120	115	102
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपए/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% (रेंज)	20-30	30-40	40-50	60-70

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों का पहुँच मूल्य, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में कम था और इसके फलस्वरूप कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है।

कम कीमत पर बिक्री

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। क्षति रहित कीमत तय की गई है और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा को तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुँच मूल्य से की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 के अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करने के बाद किया गया है।

विवरण	2015-16	
	रुपए/किग्रा.	रुपए/किग्रा.
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुँच कीमत	102.45	1.55
कम कीमत पर बिक्री	***	***
कम कीमत पर बिक्री-%	***	***
रेंज	65-75%	65-75%

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना में बहुत कम है जो कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों को दर्शाता है।

(क) कीमत हास/न्यूनीकरण

कीमत हास/न्यूनीकरण

65. इसका निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव से कीमतों में काफी हद तक हास होगा अथवा कीमतों में वृद्धि रूक जाएगी, जो अन्य प्रकार से हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की है, जिसे नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
-------	-------	---------	---------	---------	---------

आयात की पहुँच कीमत	रुपए/किग्रा.	119	120	115	102
प्रवृत्ति		100	101	97	86
निवल बिक्री प्राप्ति	रुपए/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	117	114
बिक्री की लागत	रुपए/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	112	112

66. यह देखा गया है कि आयातों का पहुँच मूल्य संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत के स्तर से बहुत कम रहा है। कम कीमत पर पाटित आयातों में घरेलू उद्योग को वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि में की लागत में वृद्धि होने के बावजूद इसकी कीमत कम करने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस प्रकार से आयातों से क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

67. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:-

(क) क्षमता और क्षमता उपयोग

68. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क्षमता	मीट्रिक टन	17,120	17,120	17,120	19,220
उत्पादन	मीट्रिक टन	8,128	8,313	8,364	8,652
क्षमता उपयोग	%	47%	49%	49%	45%
घरेलू बिक्री	मीट्रिक टन	7,791	7,870	7,948	8,375

69. यह देखा गया है कि -

- (1) घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि को देखते हुए जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है। विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई, इस प्रकार से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताओं में वृद्धि देश में इस उत्पाद की मांग में वृद्धि के अनुपात में हुई।
- (2) क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई। तथापि, याचिकाकर्ता को पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं से नुकसान हुआ है।

(3) घरेलू उद्योग के क्षमता के उपयोग को घरेलू उद्योग द्वारा अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में समर्थ नहीं होने के कारण नुकसान हुआ है।

(ख) माल सूचियां

घरेलू उद्योग के पास औसत भंडार के रूप में नोट किए गए माल भंडार की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
औसत मालसूची	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	102	110	125

70. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के पास माल भंडार में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। माल भंडार में वृद्धि की दर, उत्पादन में वृद्धि की दर से अधिक थी।

(ग) लाभ/हानि

71. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री की लागत	रु.किग्रा/.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	112	112
बिक्री कीमत	रु.किग्रा/.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	108	117	114
लाभ(हानि)/	रु.किग्रा/.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		-100	719	1,029	97
लाभ(हानि)/	रुलाख .	***	***	***	***
प्रवृत्ति		-100	525	857	523
नकद लाभ	रुलाख .	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	265	355	216
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रुलाख .	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	183	240	160

72. उपर्युक्त सूचना से यह देखा गया है कि -

(क) संबंधित उत्पाद की घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2014-15 तक वृद्धि हुई, लेकिन उसमें जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट बहुत अधिक है।

(ख) कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्ष 2014-15 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान विक्री की लागत में वृद्धि होने के बावजूद इसकी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इस प्रकार से इन आयातों से संपूर्ण क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हो रहा है।

(ग) क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और विक्री में वृद्धि हुई है, लेकिन लाभप्रदता में गिरावट आई है।

(घ) नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

73. निवेश, व्याज और कर पूर्व लाभ और नकदी के प्रवान ने वही प्रवृत्ति दिखाई है, जो लाभप्रदता की थी:

	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच अवधि
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	184	211	107

(ङ) घरेलू कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक

74. संबद्ध देश से आयाता कीमतों, लागत ढांचे में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु का पहुंच मूल्य विक्री की कीमत और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है, जो भारतीय बाजार में कीमत में कटौती तथा कम कीमत पर विक्री करने को मजबूर कर रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि को दर्शा रही थी और इस कारण से यह एक कारक नहीं हो सकता था जो घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

(च) रोजगार और मजदूरी

75. रोजगार और मजदूरी नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	107	101	100
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	110	121
प्रति यूनिट मजदूरी	रुपए/मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	107	111

76. यह देखा गया है कि रोजगार उन्हीं स्तरों पर रहा है। दी गई मजदूरी में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(छ) संवृद्धि

77. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विक्री और उत्पादन के मामले में सकारात्मक रहा था। तथापि, घरेलू उद्योग का विकास वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के मामले में नकारात्मक था।

वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
-----------------------	-------	---------	---------	---------	---------

उत्पादन	%		2%	1%	3%
घरेलू बिक्री की मात्रा	%		1%	1%	5%
बिक्री की लागत	%		4%	7%	1%
बिक्री कीमत	%		8%	8%	-3%
प्रति यूनिट लाभ निहा/	%		819%	43%	-91%
नकद लाभ	%		165%	34%	-39%
नियोजित पूंजी पर लाभ	%		5%	2%	-6%

ज. पूंजीगत निवेश प्राप्त करने की क्षमता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान क्षमताओं में वृद्धि की है और नए निवेश किए हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि बाजार में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों की संख्या और इसकी मांग के स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस देश में इस उत्पाद में और आगे निवेश की पर्याप्त संभावना है। तथापि, मौजूदा उत्पादक बहुत अधिक क्षमता संवर्धन से हट रहे हैं और नए उत्पादक इस कारण से निवेश नहीं कर रहे हैं कि मौजूदा क्षमताएं स्वतः अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

झ. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

79. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटन मार्जिन के न्यूनतम स्तर से बहुत अधिक है। संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। पाटन मार्जिन के इतना अधिक होने से पाटित आयातों के कारण ही घरेलू उद्योग की आर्थिक क्षति हो रही है।

ज. क्षति संबंधी निष्कर्ष

80. उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में स्वतंत्रण रूप में तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत की तुलना में बिक्री हुई है। इस उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त इन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत पर भी दबाव पड़ रहा है। यह देखा गया है कि इस उत्पाद की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में क्षमता के उपयोग, माल भंडार, लाभ, नकदी का प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में गिरावट आई है।

81. प्राधिकारी ने नोट किया है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की मात्रा तथा कीमत प्रभाव के कारण क्षति हुई है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभ की भी वही प्रवृत्ति रही जो लाभ की प्रवृत्ति थी। अधिकांश मानदंडों जैसे लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ के मामले में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक था। इस प्रकार से, प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ट. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

82. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने में योगदान हो सकता था। संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच नीचे दिए अनुसार की गई है।

(क) तृतीय देशों से आयात की मात्रा और कीमत

83. संबद्ध देशों को छोड़ कर अन्य देशों से आयात, मात्रा के मामले में बहुत अधिक नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके अथवा उसे क्षति की संभावना हो सके। अन्य देशों से आयात, कुल आयातों में 10 प्रतिशत से कम और भारत में कुल मांग/खपत का 2 प्रतिशत है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अन्य देशों से आयातों से क्षति हो रही है।

(ख) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा एवं विदेशी और स्वदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा

84. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए एकमात्र बाजार है जहां संबद्ध देशों से पाइत आयातों की प्रतिस्पर्द्धा प्रत्यक्ष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुओं से होती है। यह भी नोट किया गया है कि आयात की गई संबद्ध वस्तुएं और स्वदेश में उत्पादित वस्तुएं, समान वस्तुएं हैं और इनका उपयोग समान प्रयोजन/अंतिम उपयोग के लिए किया जाता है। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों एवं स्वदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती हो, का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की मांग ने क्षति अवधि के दौरान वृद्धि दर्शाई है और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान ही हुई है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग की क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

(घ) प्रौद्योगिकी का विकास

86. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रोद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती थी, को दर्शने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

87. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में बहुत अधिक संभावित गिरावट के कारण नहीं हुई है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस कारण से निर्यात निष्पादन में कोई संभावित गिरावट किसी क्षति का कारण नहीं है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट आने से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

(छ) अन्य उत्पादों की तुलना में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन ने, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा जिस सूचना पर विचार किया गया है, वह केवल विचाराधीन उत्पाद के ही संबंध में है।

ट. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान वास्तविक रूप से क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किए गए हैं:-

- (1) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में जांच की समग्र अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में क्षति की अवधि और संपूर्ण जांच अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट होती रही है।
- (2) भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- (3) भारत में पाटित आयातों के बाजार का हिस्सा, जांच की अवधि के दौरान लगभग 50 प्रतिशत रहा है, जो प्रतिशत के मामले में बहुत अधिक है और वह भी तब जब संबद्ध वस्तुओं की मांग भारत में बढ़ रही है। यह इस कारणवश हुआ है कि आयातों में भारत में बहुत अधिक मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा कर लिया है।
- (4) घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपना उत्पादन और विक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में पर्याप्त अपर्युक्त क्षमता थी। यद्यपि मांग में वृद्धि हुई थी।
- (5) घरेलू उद्योग का माल भंडार बढ़ता रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी विक्री बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आयात भारत में मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा करता रहा है।
- (6) भारत में हो रहे कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास और कीमत न्युनीकरण हो रहा है।
- (7) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर लाभ पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2013-14 तक बहुत अधिक लाभ हो रहा था और उसे नियोजित पूंजी पर अधिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा था। तथापि, विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान लाभ और प्रतिलाभ अत्यधिक घाटों और नकारात्मक स्थिति में परिवर्तित हो गए हैं।

91. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते हुए पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक ठोस कारणात्मक संबंध है।

ठ. क्षति का आकार और क्षति मार्जिन

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

विवरण	रुपए/किग्रा.	अमरीकी डॉलर/किग्रा.
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	***	***
पहुंच कीमत	102.45	1.55
क्षति मार्जिन	***	***
क्षति मार्जिन-%	***	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	65%-75%	65%-75%

ड. निष्कर्ष

93. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जिन्हें इस जांच परिणाम में दर्ज किया गया है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि:

- (1) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।
- (2) घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- (3) संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा वास्तविक क्षति पहुँचाई गई है।

३. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे:

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त और स्वस्थ प्रतिस्पद्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। यह भी माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्कों को लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इसका इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पद्धा पर दुष्प्रभाव पड़ गया होगा। तथापि, भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पद्धा पाटन-रोधी उपयों से कम नहीं होगी, विशेषकर यदि पाटन-रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति से बचाने के लिए आवश्यक राशि तक ही सीमित रखा जाए। इसके प्रतिकूल पाटन-रोधी उपयों को लागू करने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जाएगा और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पाटन-रोधी उपयोग करने से किसी भी रूप में संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से इसका उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

४. सिफारिशें

95. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:-

- (1) विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देश से भारत में इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है।
- (2) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- (3) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा वास्तविक क्षति पहुँचाई गई है।

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसके बारे में अधिसूचित किया गया था। निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त समय दिया गया था। पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू किए जाने और उसका संचालन करने तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निश्चयात्मक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई आर्थिक क्षति और खतरा होने की पुष्टि हो जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि अनंतिम शुल्क लगाना जांच की पूर्णता के लंबित होने तक पाटन से बचाने तथा घरेलू उद्योग की क्षति को रोकने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

97. अपेक्षाकृत कमतर शुल्क नियम के संबंध में प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कम के बराबर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाल अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 9 में निर्दिष्ट राशि के बराबर अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुँच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3 क, 8 ख, 9 और 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क का प्रयोज्य स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद*	वस्तुओं का विवरण**	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादन	निर्यातक	राशि (अमरीकी डालर में)	माप का यूनिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	392410	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई अन्य विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.04	किग्रा.
2	392410	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई अन्य विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	1.04	किग्रा.
3	392410	सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स	कोई अन्य विनिर्देशन	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.04	किग्रा.

*सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

**विचाराधीन उत्पाद का विवरण उपर्युक्त पैरा में दिए गए विवरण के अनुसार 13 "चाकू और शैचालय की मदों को छोड़कर सेरामिक टेबलवेयर्स और किचनवेयर्स" है।

३. आगे की प्रक्रिया

98. नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद किया जाएगा।

- (1) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उन पर, यदि प्राधिकारी द्वारा संगत माना जाएगा, अंतिम जांच परिणाम में विचार किया जाएगा।
- (2) निर्यातक, आयातक, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो इससे संबंधित जाने जाते हैं, को प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग पत्र भेजा जा रहा है, जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 40 दिनों के भीतर अपने विचार से अवगत करा सकते हैं।
- (3) कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 40 दिनों के भीतर अपने विचार से अवगत करा सकते हैं।
- (4) प्राधिकारी उस सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे जहां तक इसे आवश्यक समझा जाएगा।
- (5) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम को अधिसूचित करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए मौखिक सुनवाई कर सकते हैं।
- (6) प्राधिकारी जांच परिणाम की घोषणा करने के पूर्व पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

PRELIMINARY FINDINGS

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items”, originating in or exported from China PR.

No.14/05/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time [hereinafter also referred to as the Act] and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,1995, [hereinafter also referred to as the Rules], as amended from time to time, thereof;

2. Whereas All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and Rule *supra* for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items”, (hereinafter also referred to as Ceramic tableware and kitchenware or the subject goods),originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) alleging dumping of subject goods from subject countries and consequent injury to the Domestic Industry.
3. And whereas the Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a Notification 14/05/2016-DGAD dated 13th October, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the sub Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - i. The Designated Authority, under the above Rules, received a written application from the Applicants on behalf of the domestic industries, alleging dumping of Ceramic Tableware and Kitchenware products originating in or exported from China PR.
 - ii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*.
 - iii. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country. The Authority issued a public notice dated 13th October, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - iv. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users and the Domestic Industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of China in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*.

vi. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR (whose details were made available by the applicant) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

- a. Kangfu Ceramic Manufacturing Co.
- b. Changsha Joysaint Dishware Co. Ltd.
- c. Zibo Timestone International Co. Ltd.
- d. Shanghai Fine-V Homeware & Gifts Int'l Trade Co. Ltd.
- e. BRT Industry Co. Ltd.
- f. Hojiang Ceramic Shenzhen Co. Ltd.
- g. Shenzhen Goldenwall Ceramic Co. Ltd.
- h. Qinhuangdao Hdt Trading Co. Ltd.
- i. Karosa Chinaware (Shenzhen) Co. Ltd.
- j. Jingdezhen Amtion Porcelain Co. Ltd.
- k. Handan Fengfeng Shengyuan Ceramic Co. Ltd.
- l. Leta International Group Co. Limited
- m. Linton International Co. Ltd. (Rizhao)
- n. Guangxi Yulin City Jiachao Ceramics Co. Ltd.

vii. In response to the initiation notification, none of the exporters/producers from China have responded.

viii. China Chamber of Commerce for Import & Export of Light Industrial Products & Arts-Crafts has filed legal submissions but none of its members filed questionnaire response within the stipulated time. The party sought extension after expiry of the time limits as well as the extended time already given by the Authority. The party had not availed opportunity provided to them in timely manner. The Authority notes that anti-dumping duty investigations being time bound require detailed analysis of information filed by the exporters in order to assist the authority to arrive at a fair determination. Therefore, the request of extension by the party at a belated stage was not accepted. However, the submissions filed by the party has been considered and duly addressed appropriately in this finding.

ix. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules

- a. K.S. Overseas
- b. East Coast Distributors Pvt. Ltd.
- c. Raj Agencies
- d. YSR Industries Pvt. Ltd.
- e. Wal-Mart India Private Limited
- f. Whitegold Trading Co. Pvt. Ltd.
- g. ICC Realty (I) Pvt. Ltd.
- h. Future Retail Limited
- i. Krishna Enterprises
- j. Karma Trading

x. In response, only M/s Wal-Mart India Private Limited, an importer, has filed Importer Questionnaire responses & legal submissions.

- xi. Also, the injury submissions have been filed by M/s Hamilton Housewares P. Ltd at a very late stage of investigation. The same have been made available in the public file and also addressed appropriately in this finding.
- xii. Copy of initiation notification was also sent to known Indian producers/Associations of the product under consideration including the petitioners.
- xiii. In response, the following have filed their letters supporting the petition
 - a. Yashvi Enterprise,
 - b. Anil Fine Ceramic,
 - c. Samrat Ceramics,
 - d. Raghuveer (India) Limited,
 - e. Marvel Ceramics Private Limited,
 - f. Sea Shell Ceramics (India) Private Limited,
 - g. Mudrika Ceramics (I) Ltd.,
 - h. Shan Tablewares Private Limited,
 - i. Feather Touch Ceramics Private Limited,
 - j. Oasis Ceramics Private Limited
 - k. Tata Ceramics Limited.
- xiv. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in this Preliminary Finding Notification.
- xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis and the same were kept in the public file maintained by the Authority as per the Rules.
- xvi. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of anti-dum the data provided by the Domestic Industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvii. Non-injurious price has been determined based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xviii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 31st March 2016 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the period from April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the Period of Investigation (POI).
- xix. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, including the POI. The authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation.
- xx. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this preliminary findings.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the

investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the ‘facts available’.

xxii. ***in this preliminary finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$=Rs. 65.91.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views of the opposing interested parties

5. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- i. There is a huge quality difference between the product imported and supplied by the Domestic Industry. The quality of the PUC supplied by the domestic suppliers is not upto the mark.
- ii. The product supplied by the Domestic Industry is very basic, whereas, imported products are all machine made and has a far better finishing, there were many rejections on the goods supplied by the domestic supplier, and packing by the Domestic Industry is very poor.
- iii. The domestic suppliers do not supply goods less than a truck which leads to increase in inventories and increases days of handling more than prescribed norms of Wal-mart.
- iv. Reasons for importing goods from China
 - Quality concerns of the product supplied by Domestic Industry
 - Domestic suppliers do not have the availability of proper machinery
 - Non availability of goods quality cordierite, saggers, setters and nitride bonded silicon carbide kiln furniture.
 - Non availability of cheaper fuel like natural gas.
- v. The product under Consideration is too broad and includes heterogeneous products. As per the transaction wise import data sanitary ware and toilet seat were considered as PUC.
- vi. Spice mills and ceramic grinding parts should be excluded from the product scope because these mills are not used for standard tableware such as cups and plates.
- vii. The Authority should provide a clarification on product scope.
- viii. The domestic supplier are unable to provide “Studio Pottery”

Views of the Domestic Industry are as follows:

6. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The product under consideration is Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items, originating in and exported from China PR.
- ii. Earthen ware, bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of ceramics.
- iii. The various hard, brittle, heat-resistant and corrosion-resistant materials made by shaping and then firing a non-metallic mineral, such as clay, at a high temperature are Ceramics. Bone China is manufactured from calcium phosphate (bone ash), clay, feldspar and quartz powder.
- iv. Subject goods are classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975 however imports are taking place under various subheadings at 6 and 8 digit level under HS code 6911 & 6912. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the proposed investigations. Study of the import data shows that subject goods have been imported into India under the various Customs sub-headings such as 6911, 691110, 69111011, 69111019, 69111021, 69111029, 69119010, 6912, 69120010, 69120020, 69120030, 69120040
- v. The product has various properties such as powerful hydrophobic and oleo phobic properties, enormous non-stick properties, hygiene protection for ceramic surfaces, strong abrasion resistance,

short drying period, can be stored directly after application, resistant to temperature change, drying at room temperature, chemical and abrasion resistant, high efficiency through economical use (consumption: 5-10 ml per m²), food safe, environment-friendly, completely frost proof

- vi. The subject goods produced by the Domestic Industry are identical to the product under consideration being imported into India. The Domestic Industry claims that there is no known difference in applicant's product and product under consideration exported from the subject country and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.
- vii. The claim of exporter regarding their quality being far superior is strongly refuted. There is no difference in the technology employed. Indian industry is fitted with best of the machines viz roller heads, auto cup plants and equipped with latest state of art, fuel efficient and environment friendly kilns. Kiln furniture, seggars, raw materials, China clay etc. of best quality is readily available. In fact, Indian produced Kiln furniture and raw material is so good in quality that it is being exported to various countries. Difference in quality is not a sufficient justification for exclusion of a product as has been held by the Designated Authority and upheld by the Hon'ble CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority.
- viii. The scope of the Product under consideration is not broad but similar as other investigations such as Opal Glassware, Melamine products, Ceramic Insulators.
- ix. As per WTO decision the Designated Authority is free to define the Product under consideration in a manner deemed appropriate and proper.
- x. If the imported goods are of better colours and designs or are more innovative, it should certainly have better prices than the domestic producers, but it is not so in the present case.
- xi. The allegation of rejection of domestic products is completely baseless. Walmart still buys Ceramic tableware from the domestic producers.
- xii. Domestic Industry is manufacturing and supplying STUDIO pottery to many Indian Retail chains like Future Group (Big Bazar), Lifestyle, Good earth, Shoppers Stop etc.

Examination by Authority

7. The product under consideration in the present investigation is defined as "Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items" (hereinafter referred to as 'subject goods' or PUC).

8. It is noted that bone china, stoneware and porcelain-ware all constitute ceramic products and therefore the product under consideration includes kitchenware and tableware of bone china, stone and porcelain. Ceramic tableware and kitchenware products are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages and for decoration in homes and hotels.

9. The product under consideration is not produced in various grades having any significant difference in the associated cost. Various types of the product, such as spoons, bowls, plates, etc. are produced from the mixture of calcium, quartz, feldspar and china clay. Production of different types merely implies forming this mixture into desired shape. Therefore, it is considered appropriate to classify all these items under a broad heading of "Ceramic Tableware and Kitchenware products". There has been a similar kind of case for the product called "Opal Glassware of all types" and "Melamine Tableware and Kitchenware products".

10. As regards the argument of supply of Studio Pottery by the petitioners, it is noted that the petitioners have provided evidence of supply of studio pottery. The claim of the interested parties is found factually incorrect. The Authority notes that the definition and scope of PUC is clearly provided in the initiation notification and also in this provisional finding regarding the PUC.

11. The Authority has decided that it would be appropriate to express PUC in terms of weights because at import end as well as factory to dealer end the transactions are mainly done in weight terms. Further, it has been seen that more than 50-60% of the cost of the product is on account of raw material and utilities. The cost of the raw material and utilities is in direct proportion to the weight of the product; therefore, the cost of

production is quite linear with weight of the product. The majority of DGCIS data is available in weight terms and all the analysis has been done on the basis of weight.

12. Subject goods do not have a dedicated classification and is classified under Chapter 69 of Customs Tariff Act, 1975. It is imported under various subheadings under HS code 6911 and 6912. However, the HS codes are indicative only and product description is the determining factor for the purpose of present investigation.

13. Therefore, the PUC under the present investigation is “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items”

LIKE ARTICLE

14. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

“an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation”.

15. As argued by the other interested parties about the quality, design of the product manufactured by the Domestic Industry and those imported in to India, it is noted that there is no quantified evidence provided by interested parties to show the alleged quality difference between the domestic and imported product. The authority notes that a difference in quality cannot be recognized, unless the differences are quantified and their impact demonstrated. The authority also notes the decision of the CESTAT in the matter of “DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority”, reported in 2000 (119) E.L.T. 308, where the Tribunal held as follows

“As the plea of the appellants counsel is not convincing since he did not adduce any evidence/technical literature with reference to process of manufacture to show that product manufactured by the domestic manufacturers was different from that exported into India. Difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles.”

16. As regards the argument of reasons of importation of goods, it is noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers

17. After considering the information on record, the Authority holds that there is no material difference in product under consideration exported from subject country and the product produced by the Indian industry. Product under consideration produced by the Domestic Industry is comparable to the imported subject product in terms of physical & chemical characteristics, production technology & manufacturing process, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable.

18. Thus, the Authority holds that product under consideration produced by the applicant Domestic Industry is like article to the subject product under consideration imported from subject countries in accordance with the AD Rules

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

View of the opposing interested parties

19. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- The anti-dumping application is filed in clear violation of Rule 5 of the Ant Dumping rule.
- The support letters filed by various domestic producers cannot be relied on because on close perusal of the letters it can be seen that the support letter were filed for different anti-dumping investigation

filed by different set of producers. On that account the applicants cannot be said to be the Domestic Industry.

- iii. The investigation should be terminated on the account that it has no express support from the industry.
- iv. The applicants collectively constitute only 30% of the domestic producers, hence not eligible for Domestic Industry.
- v. The Authority could have added other known domestic producers to understand the trend of the Indian producers as a whole.
- vi. Even if the total production of the applicants is more than 25% but that is relevant with regard to standing of the application and not for the purpose of defining the scope of the Domestic Industry.

View of the Domestic Industry

20. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The petition is jointly filed by All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) on behalf of domestic producers of the PUC in India. Some of the Indian Producers i.e. Clay Craft (I) Pvt. Ltd., Bharat Potteries Ltd., Ceramic Tableware Ltd. and U.P. Ceramics & Potteries P. Ltd. (referred to as Petitioner/Applicant) for imposition of anti-dumping duty on imports of Ceramic tableware and kitchenware, excluding knives and toilet items, originating in and exported from China PR.
- ii. Besides the petitioners, some producers have supported the petition. Letters of support from Yashvi Enterprise, Anil fine Ceramic, Samrat Ceramics, Raghuvir (India) Limited, Marvel Ceramics Private Limited, Sea Shell Ceramics (India) Private Limited, Mudrika Ceramics (I) Ltd., Shan Tablewares Private Limited, Feather Touch Ceramics Private Limited, Oasis Ceramics Private Limited and Tata Ceramics.
- iii. The petitioners account for more than 30% of the Indian production. Further they have got support from number of manufacturers taking the total share of production percentage to more than 60%; therefore petitioner companies constitute major proportion in the total Indian production and are covered within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules as.
- iv. Petitioners have not made any imports and nor are related (either directly or indirectly) to any exporter of product under consideration in the subject country or importers in India.
- v. The supporters have consciously supported the petition for imposition of anti-dumping duties on imports of Ceramic kitchenware and tableware from China PR as per AD Rules.

Examination by Authority

21. Rule 2 (b) of the AD rules defines Domestic Industry as under:

"(b) "Domestic Industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

22. The petition has been filed by All India Pottery Manufacturers' Association (AIPMA) and the Indian Ceramic Society (herein referred as petitioners/ petitioner associations) on behalf of domestic producers of the PUC in India. Some of the Indian Producers i.e. (a) Clay Craft (I) Pvt. Limited, (b) Ceramic Tableware Pvt. Ltd., (c) Bharat Potteries Ltd. and (d) M/s. UP Ceramics & Potteries Pvt. Ltd. (referred as petitioners/ petitioner companies) have provided the necessary costing and financial information. The petition has been supported by a number of other producers, namely, Yashvi Enterprise, Anil Fine Ceramic, Samrat Ceramics, Raghuvir (India) Limited, Marvel Ceramics Private Limited, Sea Shell Ceramics (India) Private Limited, Mudrika Ceramics (I) Ltd., Shan Tablewares Private Limited, Feather Touch Ceramics Private Limited, Oasis Ceramics Private Limited and Tata Ceramics Limited.

23. The total Indian production has been estimated on the basis of data given by Central Glass & Ceramic Research Institute (CSIR). They have mentioned details of producers of the product in the organized sector as well as in the unorganized sector.

Particulars	MT	Share in Indian Production %
	POI	POI
Petitioner as a whole	8,652	31%
Supporters as a whole	8,650	31%
Petitioner + Supporter as a whole	17,302	62%
Others	10,700	38%
Indian Production	28,002	100%

24. Further, the petitioner companies have certified that they have neither imported the product under consideration from subject country, nor are they related to any exporter of the product under consideration in subject country or to an importer in India.

25. As per the evidence available on record, the production of the petitioner companies accounts for a major proportion in the gross domestic production of the like article. The Authority, therefore, determines that the petitioner companies constitutes eligible Domestic Industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. CONFIDENTIALITY

View of the opposing interested parties

26. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- Excessive confidentiality is claimed by the applicants and has not provided information with regard to Production volume, Domestic Sales volume, Export Sales volume, Inventory in volume, COP per unit in Indexed, Selling price per unit in Indexed (g) Profit/(Loss)per unit in Indexed (h) Employment, Productivity, ROCE in percentage, Proforma IV-B, Costing information and ROC version of financial results.
- Not providing such information is completely against the confidentiality provisions provided under the Anti-Dumping Rules. Considerable information has been kept confidential without providing any justification for the same.

Views of the Domestic Industry:

27. The Domestic Industry made the following submissions

- The Domestic Industry has claimed confidentiality as per the norms of the AD Rules and in fact the opposite interested parties have claimed excessive confidentiality and made it difficult to make proper comment on their submission.

Examination by Authority

28. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

29. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

30. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. Various discussions in this provisional finding are self-explanatory on the other contentions of the Domestic Industry on confidentiality aspect.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Views of the opposing interested parties

31. The submissions of various interested parties are summarized as follows:

- i. The petition was filed in January 2016 and the data is provided till March 2016. This clearly shows that the Authority has not examined the adequacy and accuracy of the data provided by the applicants.
- ii. The domestic producers have failed to provide their information despite having notice of the instant investigation, should be treated as non-cooperative under Rule 6 (8) of the Anti-dumping Rule.
- iii. The supporters, who have failed to provide information, show that they have only made unsubstantiated claim of injury before the Authority.
- iv. The methodology adopted for conversion of import volume and volume analysis is based on unsupported presumption. The PUC has been measured/quantified in terms of weight whereas the import statics reflects that majority of imports are reported in units/pieces.
- v. The Authority has acted in contravention of Article 12.1 of the Anti-Dumping Agreement because it failed to inform the interested parties before initiation that the Authority is satisfied and there are sufficient evidences to justify the initiation of the investigation.
- vi. The petitioners have failed to provide the sources of information relied upon for dumping and injury determination.
- vii. The DGCI&S data in Excel format both in raw and refined form along with the methodology applied has not been provided.

Views of the Domestic Industry:

32. The Domestic Industry made the following submissions

- i. The Chinese exporters have not cooperated by not filing any information despite given an opportunity after initiation of the investigation. None of the exporters have filled exporter questionnaire.

- ii. Chinese producers/exporters Association, responsible for assisting the exporters in defending their case in anti-dumping matters, have also not cooperated by providing detailed information pertaining to costing and exports. The Chinese Association should be considered as non-cooperative
- iii. The petitioners have adopted the DGCI&S import data, the same has been provided in the NCV copy of the petition. A large share of imports is in weight terms and the other units namely numbers/pieces/sets have been converted into weight terms for effective analysis of whole of import data. Further PUC is transacted in weight terms at factory level. Therefore, the adoption of unit of measure as weight is appropriate and the opposite party has objected to the same without providing any alternative methods.
- iv. The Authority had notified all the interested parties about the initiation of the present investigation by notification.
- v. The necessary costing/financial information has been provided by the petitioner domestic industry as prescribed under the law. The supporters who are also suffering the effects of dumping and have supported the petition are not specifically required to give their costing/financial data.
- vi. The export price from China PR has been determined as per the DGCI&S transaction wise data with due adjustments to the export price as per the market intelligence and standard practices.

Examination by Authority

33. Various submissions have been made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- i. The Authority notes that the application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority after due examination decided to initiate the present investigation and had also revised the Period of Investigation to April 15-March 16. The revised application was sought, subsequent to initiation, and NCV was made available in public file. The information given by the applicant was verified to the extent deemed necessary.
- ii. The Authority has decided that it would be appropriate to express PUC in terms of weights because at import end as well as factory to dealer end the transactions are mainly done in weight terms. The cost of the raw material and utilities is in direct proportion to the weight of the product; therefore, the cost of production is quite linear with weight of the product. The majority of DGCI&S data is available in weight terms and the balanced data available in numbers/sets/pieces has been converted into weight and all the analysis has been done in terms of Kgs.
- iii. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra. Further, the Authority has issued a notification, published in the Gazette of India, extraordinary notifying the initiation of investigation.
- iv. As regards the argument that the other domestic producers have not provided the information or the supporters have filed the limited information, it is noted that as per AD Rules, the injury analysis has to be carried out on the basis of the information provided by the Domestic Industry. In the instant case, once it is determined that the petitioner companies constitute Domestic Industry, there is no legal requirements under the AD Rules to rely on the information of the other Indian producers.
- v. The Authority notes that the DGCI&S transaction by transaction wise data was made available in the public file being a part of the NCV petition. For the analysis data has been duly verified as deemed fit. Further, the various calculations for determination of NEP and landed value as mentioned in the subsequent paras has been carried out after as per the methodology and standard practices followed in the Directorate on the basis of best available information.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

Market Economy Treatment and Normal Value

34. According to Section 9A (1) (c) of the Customs Tariff Act, 1975 'Normal Value' in relation to an article means: -

comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either—

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Views of the Domestic Industry:

35. The following are the submissions made by the Petitioner:

- i. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries. Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii. Market economy status cannot be granted unless following conditions are fulfilled:
 - a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
 - b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.
 - c. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards.
 - d. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.
 - e. The onus/obligations to establish market economy status is onto responding Chinese exporters and not onto the Designated Authority.
 - f. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim.
 - g. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- iii. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:
 - the price in a market economy third country,
 - constructed value in a market economy third country,
 - the price from such a third country to other country, including India.
 - the price actually paid in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
 - the price actually payable in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- iv. Since no questionnaire response has been filed by any of the Chinese companies, the subject country should be treated as non-market economy.

v. The export price from China PR has been determined as per the DGCI&S transaction wise data with due adjustments to the export price as per the market intelligence and standard practices.

Views of the opposing interested parties

36. The views of the opposing interested parties are summarized as follows:

- Methodology adopted by the petitioners and envisaged by DA to determine normal value is in contravention to the provisions laid down under Para 7 of Annexure 1 of the AD Rules.
- The determination of export price and adjustments therein, done to the export price have been made without any evidence.

Examination by the Authority

Provisions relating to Non- Market Economy countries

37. The Authority notes that the relevant provisions laid down under Annexure-I to AD rules states as under:

7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments;

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3);

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country;

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3);

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and;

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”

38. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of nonmarket economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in their country to provide the relevant information. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.

39. The Authority notes that none of the producers and exporters of the subject goods from the subject country have submitted the exporter's questionnaire response and market economy questionnaire response, consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. In view of the above position, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. As none of the producers/exporters from China PR has submitted MET questionnaire response, the Authority is unable to grant market economy status to Chinese producers for the purpose of proposed determination.

40. In view of the fact that none of the producers/exporters has filed any exporter's questionnaire including MET questionnaire, MET status has not been accorded to Chinese producers. Further, none of the interested parties, including the Domestic Industry, has made available any material fact to the Authority to select an appropriate market economy third country. The Authority has, therefore, determined the normal value in respect of China PR on other reasonable basis, in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

41. In view of the above, the normal value for the subject products imported from China PR into India has been determined on the "any other basis" by considering best available information with regard to cost of production and after reasonable additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value has been constructed considering consumption of major raw materials conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the most efficient constituent of the Domestic Industry. 5% of cost of sales excluding interest has been added towards reasonable profit. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration is as shown in the dumping margin table below.

Determination of Export Price for exporters from China PR

42. The Authority notes that none of the exporters have furnished information to the authority in the form and manner prescribed which could be used for determination of the export price and individual dumping margin. Therefore, the Authority has determined the export price for producers/exporters on the basis of the DGCI&S transaction wise data.

43. The export price has been adjusted on account of Ocean Freight, Marine Insurance Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from China PR is as shown in the dumping margin table below.

Determination Of Dumping Margin

44. Based on the methodology explained above, the normal value, export price and dumping margin in respect of all producers/exporters of the subject country is determined as follows.

Particular	POI	
Constructed Normal Value	Rs/KG	\$/KG

Net Export Price	***	***
Dumping Margin	86.17	1.31
Dumping Margin - %	***	***
Dumping margin % (Range)	***	***

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the opposing interested parties

45. The submissions of various interested parties considered relevant by the Authority are summarized as follows;

- i. There is no volume injury to the Domestic Industry. The demand of the subject goods have increased by 3% in the Period of investigation however the sale has increased by 12% in the Period of investigation. The industry has performed exceptionally well in terms of domestic sales.
- ii. The producer whose performance has deteriorated has not assisted the Authority in arriving at a fair determination by not providing the requisite data/information.
- iii. The applicants have been able to sell 93% of their total production in Period of investigation. Hence suffering no injury.
- iv. The domestic producers are unable to meet the domestic demand for the subject good. The import of the subject good has increased to the extent of decrease of sale of the other domestic producers.
- v. Imports were made to bridge the demand supply gap. The domestic producers are suffering injury due to inefficiency of filling the demand supply gap in the domestic market.
- vi. There is no price injury. The methodology adopted by the applicants to arrive at the weight of the subject good exported in units/pieces and the consequent price of the dumped article is flawed.
- vii. There is no price suppression or depression on account of imports. The net sales realization of the applicant is higher in comparison to the cost of the subject good.
- viii. The applicants have been able to increase their selling price as compare to the increase in the cost of the price.
- ix. Working capitals of the applicants have almost doubled during the injury period. Such increase in working capital is unreliable and unsubstantiated.
- x. There is no causal link between the alleged dumping and injury to the domestic market. The applicants have enhanced capacities anticipating increase in demand but the demand remained constant during the examination of injury period.
- xi. There is no injury to the other producers of the domestic market and they are performing exceptionally well but they have not been included under the list of domestic producers.
- xii. The applicants have failed to provide any evidence to show that the Domestic Industry is suffering injury due to alleged dumping.
- xiii. The material injury or threat of injury to the domestic injury is based only on allegation, statement or conjecture
- xiv. There is a price hike every six months
- xv. There have been instances where domestic suppliers have delivered good less than what was ordered and were not able to supply goods to Wal-mart within the prescribed period.

- xvi. As per the information provided by the DI in the petition the market shares of the Domestic Industry increased by 24% in the Period of investigation. Demanding anti-dumping duty on the ground that increase in demand is slow is completely unwarranted and unjustified.
- xvii. There is price undercutting because the indexed Net sales Realization has increased from 100 /- per Kg in 2012-13 to 106/- per kg during the Period of investigation.
- xviii. The alleged dumped import has no effect on the price of the Domestic Industry. The petitioners have failed to prove price undercutting or price depression or suppression.
- xix. Cost of sales has also increased during the Period of investigation.
- xx. The production of the petitioners has increased steadily during the Period of investigation and domestic sale has also increased.
- xxi. There is slight decline in the capacity utilization but that is not due to the alleged dumping but on account of increased installed capacity.
- xxii. Petitioners have moved from being loss making in 2012-13 to being hugely profitable units from 2013-14 onwards to the Period of investigation.
- xxiii. The wages have increased during the Period of investigation. There are none of economic factors appear to have been adversely affected directly on account of alleged dumping of the PUC in India.
- xxiv. The applicants have not been able to provide evidences for threat of material injury or any of the factors of threat of material injury is present due to alleged dumping.
- xxv. The Authority has discussed in their final findings like Anti-Dumping investigation concerning imports of certain Polyester Staple Fibers originating and exported from Korea R P, Malaysia, Taiwan and Thailand, and Final finding of Floor Glass originating in and exported from People's Republic of China, and Indonesia and the Authority has highlighted the importance of economic parameters and has held that mere existence of dumping is not sufficient for imposing anti-dumping duty. Other known factors must also be examined which are causing injury to the Domestic Industry.
- xxvi. The installed capacity of the applicants was low as compare to the demand in the domestic market. Imports were made to meet the deficit arising out of demand supply gap.
- xxvii. The domestic industry is performing well and earning profits. Mere price undercutting is not sufficient to determine injury to the domestic industry.
- xxviii. The profits of the domestic industry have increased during POI as compared to base year. There is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the domestic industry.

Views of the domestic industry

- 46. The following are the injury related submissions made by the Domestic Industry in brief;
 - i. There has been increase in demand over the injury period.
 - ii. The volume of import of the subject goods from the subject country has increased significantly over the injury period. The subject imports have almost doubled from base year to proposed POI. Imports from China have increased significantly in relation to total imports, as well as consumption and production in India over the injury period.
 - iii. Market share of Domestic Industry has increased slightly; whereas market share of Indian producers has declined. On the other hand, market share of subject imports has increased significantly over the injury period. The domestic industry could not capitalize the increase in demand.
 - iv. The subject imports are undercutting the domestic prices and price undercutting has increased over the injury period. Landed price of imports have remained significantly below the cost of sales of the Domestic Industry over the injury period;
 - v. Landed price of imports have increased in 2013-14 and then declined over the injury period, whereas selling price of the Domestic Industry have increased up to 2014-15 and then declined in the POI succumbing to the price depression effect of dumped imports;

- vi. Production and sales of the Domestic Industry have increased over the injury period. However, this increase in production and sales volume is insignificant considering the level of capacities available and demand in the country.
- vii. Capacity has remained under-utilized in the proposed injury period due to significant dumping being resorted by the foreign producers, resulting in lower volume of sales by Indian producers.
- viii. Despite availability of sufficient domestic production capacity, consumers continued to meet their demand with dumped imports from the subject country resulting in sub-optimal performance in terms of volume parameters.
- ix. Profitability increased during the injury period. However, there was a significant drop in the Period of investigation as compared to the previous year. Similar trend were followed in performance of the Domestic Industry with regard to profit, cash flow and return on capital employed. However, the inventories increased and the cost of sales increased putting a pressure on the health of the domestic industry.
- x. Market share of imports from other countries has remained very low throughout the proposed injury period whereas market share of subject imports has increased significantly over the injury period. Market share of imports from other countries has remained very low throughout the proposed injury period.
- xi. Productivity of the Domestic Industry, measured in terms of production per employee has increased. The level of employment with the Domestic Industry has increased up to 2013-14 and then declined. Wages have increased up to 2014-15 and then declined in the proposed POI.
- xii. Inventories of the product under consideration with the Domestic Industry increased significantly over the injury period.
- xiii. Growth of the Domestic Industry in terms of volume and price parameters has remained sub-optimal. Both dumping margin and injury margin in the proposed POI are positive and significant.
- xiv. Indian Industry has sufficient capacity to cater to the Indian demand. But Indian industry is unable to improve capacity utilization due to presence of dumped imports. Demand supply gap cannot justify dumping. The foreign producers should not dump the goods in order to meet Indian demand.
- xv. The opposite party is pointing out the demand supply gap and on the other hand raising questions on enhancement of capacity. The capacity was enhanced because the demand increased throughout the injury period.
- xvi. The injury is due to dumped imports because the volume of dumped imports have captured the market share of the Domestic Industry, undercutting prices, price depression, deteriorated profit, has prevented the industry from increasing its production, sales, capacity utilization. Growth parameters have been affected negatively.
- xvii. The marketing channel of the subject good is such that the domestic producers need to sell the product through large network which makes it impossible for them to reduce the price of the good and if the Chinese imports are cheaper then it will obviously attract more consumer resulting into more imports. It is not the eventual consumers who are getting benefitted with so significantly low priced imports.
- xviii. The opposing interested parties have not pointed out other reasons which can cause injury to the Domestic Industry.
- xix. The allegation of price hike is baseless. The question is how many time price hikes are accepted by Walmart. The Domestic Industry claimed price increase based on inflationary trend of varied cost factors and exchange rate fluctuations in prices of raw material, that too, once in a year or two years.

Examination by the Authority

47. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties on injury. The issues raised by various interested parties have been dealt with in the relevant paras of this disclosure.

48. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.

49. As regards the contention that the Domestic Industry does not have sufficient capacity to meet the demand of product under consideration in the country, the authority notes if there is a demand supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price. Demand supply gap does not justify dumping of the product.

50. For the purpose of injury analysis the Authority has examined effect of dumped imports of the subject goods on the Domestic Industry and its effect on all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry to evaluate the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

i. Volume Effect Of The Dumped Imports On The Domestic Industry

a. Import volumes

51. The authority has relied upon import data procured from DGCI&S in the present investigation. The Authority has considered weight as an appropriate unit of measurement. The examination of data received from DGCIS revealed that about 46% of the total transactions in POI are those where import volumes have been reported on weight basis. However, the balance imports are in various other units namely numbers, sets, dozens, pieces and Kgs. The import transactions on weight basis have been adopted as it is for analysis. The per unit average import price has been determined by considering the import value and volume of the transactions reported on weight basis. The per unit average import price, so determined is considered while converting those transactions which are reported in units other than weight, into weight thereby 100% of the reported import transactions have been considered for analysis. Imports volume from subject country were as under:-

Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Other Countries	MT	849	972	810	836
Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996

52. It is seen that imports from subject country have increased significantly in absolute terms over the injury period.

b. Demand and market share

53. The demand/apparent consumption of subject goods has been determined by adding domestic sales and import of subject goods from all countries.

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Sales of Domestic Industry	MT	7,791	7,870	7,948	8,375
Sales of Other Indian Producers	MT	19,752	18,361	16,795	15,269
Sales of Indian Producers	MT	27,543	26,231	24,743	23,644
Imports from China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Other Countries – Imports	MT	849	972	810	836
Demand/consumption	MT	33,911	33,799	34,667	34,640
Market Share in Demand					
Domestic Industry	%	23%	23%	23%	24%
Other Indian Producers (including supporters)	%	58%	54%	48%	44%

Indian producers as a whole	%	81%	78%	71%	68%
China	%	16%	20%	26%	29%
Other Countries	%	3%	3%	2%	2%

54. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased during POI as compared to the base year and also showing an overall positive trend over the entire injury period. Whereas the demand for the product under consideration increased by 2% from base year, imports from China increased by 84% over the same period.

55. It is thus seen that share of imports from subject country in Indian demand increased from 16% to 29% over the injury period. The market share of Domestic Industry has remained constant but the market share of the Indian industry as a whole has declined significantly.

ii. Share of dumped imports in relation to production

56. Authority observes that the imports from subject country have increased in relation to production in India as shown below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Imports from China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Total Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996
Production of the Domestic Industry	MT	8,128	8,313	8,364	8,652
Indian Production	MT	30,510	30,069	28,283	28,002
Share of subject country imports in relation to					
Domestic Industry Production	%	68%	79%	109%	117%
Indian Production	%	18%	22%	32%	36%

a. Imports in relation to total imports

57. Imports of the product under consideration from subject country have increased in relation to total imports into India.

Imports	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
China	MT	5,519	6,596	9,114	10,160
Other Countries	MT	849	972	810	836
Total Imports	MT	6,368	7,568	9,924	10,996
Share in Total Imports					
China	%	87%	87%	92%	92%
Other Countries	%	13%	13%	8%	8%

58. It is, thus, concluded that the share of imports from subject country have captured the market share and increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India

H. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

60. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the Domestic Industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

61. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the Domestic Industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the Domestic Industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the Domestic Industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Landed price of imports	Rs./KG	119	120	115	102
Net Sales Realization	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting (%)	%	***	***	***	***
Price undercutting	%(Range)	20-30	30-40	40-50	60-70

62. The Authority notes that the landed price of imports from the subject country was lower than the selling price of the Domestic Industry, thus resulting in significant price undercutting.

Price Underselling

63. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been determined considering the cost of production of the Domestic Industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules.

Particular	2015-16	
	Rs/KG	\$/KG
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	102.45	1.55
Price underselling	***	***
Price underselling-%	***	***
Range	65-75%	65-75%

64. The Authority notes that the landed price of the subject goods from the subject country is significantly lower than the NIP determined for the Domestic Industry showing price underselling effects.

a) Price suppression/depression

Price suppression/depression

65. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period as below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Landed price of imports	Rs./KG	119	120	115	102
Trend		100	101	97	86
Net Sales Realization	Rs./KG	***	***	***	***
Trend		100	108	117	114
Cost of Sales	Rs./KG	***	***	***	***
Trend		100	104	112	112

66. It is seen that landed value of imports have remained significantly below the level of cost of sales and selling price of the Domestic Industry throughout the injury period. Low priced dumped imports forced the Domestic Industry to reduce its prices despite increase in cost of sales in period of investigation as compared to 2014-15. Thus the imports are depressing the prices of the Domestic Industry throughout the injury period

ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

67. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below.

a. Capacity & Capacity Utilization

68. Capacity and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Capacity	MT	17,120	17,120	17,120	19,220
Production	MT	8,128	8,313	8,364	8,652
Capacity Utilization	%	47%	49%	49%	45%
Domestic Sales	MT	7,791	7,870	7,948	8,375

69. It is observed that:

- Domestic Industry has enhanced its capacity during period of investigation, in view of the increase in demand. Demand for the product under consideration increased over the injury period. It is thus seen that the enhancement in capacities by the Domestic Industry was commensurate with the increase in demand for the product in the Country.
- Production and sales of the Domestic Industry increased over the injury period, however, the petitioner is suffering significant unutilized capacities.
- Capacity utilization of the Domestic Industry has suffered as a result of the inability of the Domestic Industry to increase its market share.

b. Inventories

The position of inventories noted as average stock with the Domestic Industry moved as follows;

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend		100	102	110	125

70. It is noted that inventories with the Domestic Industry have increased significantly over the injury period. The rate of increase in inventories was more than the rate of increase in production.

c. Profit/Loss

71. The profitability of the Domestic Industry is given in the following table:

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Cost of sales	Rs/KG	***	***	***	***
Trend		100	104	112	112
Selling price	Rs/KG	***	***	***	***
Trend		100	108	117	114
Profit/(Loss)	Rs/KG	***	***	***	***
Trend		-100	719	1,029	97
Profit/(Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		-100	525	857	523
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		100	265	355	216
Profit before Interest and Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend		100	183	240	160

72. It is seen from the above information that:

- The profitability of the Domestic Industry with respect to domestic sales of the product concerned increased till 2014-15 but deteriorated significantly during POI. The decline in profits of the Domestic Industry is very significant.
- Low priced dumped imports forced the Domestic Industry to reduce its prices despite increase in cost of sales during the period of investigation as compared to 2014-15. Thus the imports are depressing the prices of the Domestic Industry throughout the injury period
- The production and sales increased over the injury period but the profitability declined.
- Return on capital employed**

73. The returns on investment, PBIT and cash flow have followed the same trend as that of profitability

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	184	211	107

e. Factors affecting domestic prices

74. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the

subject country is below the selling price and the non-injurious price of the Domestic Industry, causing significant price undercutting as well as price underselling in the Indian market. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period including the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from subject countries.

f. Employment and Wages

75. The employment and wages are below:

Particulars	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
No of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend		100	107	101	100
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		100	104	110	121
Wage per unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend		100	101	107	111

76. It is seen that the employment has remained at the same levels. Wages paid have increased during period of investigation.

g. Growth

77. The Authority notes from the table below that growth of the Domestic Industry was positive in terms of sales and production on year to year basis. However, growth of the Domestic Industry was however negative in respect of profits, cash profit and return on investment on year to year basis.

Growth (Year by Year)	Units	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Production	%		2%	1%	3%
Domestic Sales Volume	%		1%	1%	5%
Cost of sales	%		4%	7%	1%
Selling price	%		8%	8%	-3%
Profit/Loss per unit	%		819%	43%	-91%
Cash Profits	%		165%	34%	-39%
Return on Capital Employed	%		5%	2%	-6%

h. Ability to raise capital investment

78. The Authority notes that the Domestic Industry enhanced capacities during period of investigation and made fresh investments. The Domestic Industry contended that given the level of demand and number of producers of the product under consideration in the market, it is evident that there is significant scope for further investment in the product in the Country. However, the existing producers are staying away from significant capacity addition and new players are not joining for the reason that the existing capacities itself are remaining unutilized.

i. Level of dumping & dumping margin

79. The Authority noted that the imports from the subject country are far above the de minimis level of dumping margin. The dumping margin for subject country is quite significant. With such high magnitude of dumping margin, dumped imports are causing material injury to the Domestic Industry.

I. CONCLUSIONS ON INJURY

80. Based on the above, the Authority provisionally concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India. Imports of the product are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market. Further, the imports were depressing the price of the Domestic Industry. It is observed that the demand for the product increased significantly and consequently production and sales of the Domestic Industry also increased, however, performance of the Domestic Industry deteriorated in respect of capacity utilization, inventories, profits, cash flows and return on investments.

81. The Authority noted that the Domestic Industry has suffered injury on account of volume as well as price effect of dumped imports, as a result of which the profitability of the Domestic Industry has declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Growth of the Domestic Industry in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, returns on capital employed, etc. was negative. Thus, Authority concluded that the Domestic Industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

82. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the Domestic Industry. The examination of causal link between dumping from subject countries and material injury to the Domestic Industry has been done as follows:

(a) Volume and prices of imports from third countries

83. The imports from the countries other than the subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the Domestic Industry. Imports from other countries accounted for less than 10% in total imports and 2% of total demand/consumption in India. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

(b) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

84. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the Domestic Industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the Domestic Industry.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

85. The Authority notes that demand for the product showed increase during the injury period and also during the POI as compared to base year. Thus, it can be concluded that the injury to the Domestic Industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

86. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

(e) Export performance of Domestic Industry;

87. The Domestic Industry is primarily for sale of goods in the domestic market. However, the domestic sales and export performance has been separately analysed. It is clear that claimed injury to the Domestic Industry is not on account of any significant change in export performance of the Domestic Industry.

(f) Productivity of the Domestic Industry

88. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the Domestic Industry.

(g) Performance of the Domestic Industry with respect to other products

89. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry has not affected the Domestic Industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

90. Analysis of the performance of the Domestic Industry over the injury period shows that the performance of the Domestic Industry has materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the Domestic Industry is established on the following grounds:

- i. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject countries have increased in absolute terms. Also, the landed price of imports has been declining significantly over the injury period and through the POI.
- ii. Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.
- iii. Market share of dumped imports in India remained at about 50% during the POI which is a significant percentage and that too when the demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the robust demand in India.
- iv. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand. The Domestic Industry had significant unutilised capacity in the POI even though the demand had increased.
- v. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise, as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- vi. There is significant price suppression and depression due to low priced dumped imports coming in to India.
- vii. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. This is evident from the fact that the Domestic Industry was earning decent profits and return on capital employed till 2013-14. However, especially during the POI, the profits and returns have turned into huge losses and negative situations.

91. The above analysis indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India from subject countries. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from subject countries and the material injury suffered by the Domestic Industry.

L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

92. The Authority has determined non-injurious price for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country. The injury margin so determined is significant.

Particulars	Rs/Kg	USD/Kg
Non Injurious Price (NIP)	***	***
Landed Price	102.45	1.55
Injury Margin	***	***
Injury Margin-%	***	***
Injury Margin (Range)	65%-75%	65%-75%

M. CONCLUSIONS

93. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority provisionally concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value, resulting in dumping.
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country.
- iii. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES:

94. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the downstream products and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti- dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the Domestic Industry. On the contrary, imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

O. RECOMMENDATION

95. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- i. The product under consideration has been exported to India from subject countries below their normal values.
- ii. The Domestic Industry has suffered material injury.
- iii. Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from subject countries.

96. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and causal links in terms of the provisions laid down under the Anti-dumping Rules and having provisionally established positive dumping margin as well as material injury to the Domestic Industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

97. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col No.9 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S.N	Tariff Item*	Description of Goods**	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	Unit of measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	392410	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any specification	China PR	China PR	Any	Any	1.04	KG
2	392410	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any specification	China PR	Any	Any	Any	1.04	KG
3	392410	Ceramic Tablewares and Kitchenwares	Any specification	Any	China PR	Any	Any	1.04	KG

*Custom classification is only indicative and the determination of the duty shall be made as per the description of PUC.

** **Description of the Product** under consideration is “Ceramic table wares and kitchen wares, excluding knives and toilet items” as detailed in para 13 above.

N. FURTHER PROCEDURE

98. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- Exporters, importers, the applicant and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within forty days from the date of the publication of these preliminary findings.
- Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- The Authority may hold oral hearing to hear the interested parties orally before notifying the final findings.
- The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing the final findings.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority